भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1967
जिसका उत्तर बुधवार 2 अगस्त, 2017 को दिया जाना है

**बिजली से चलने वाले वाहनों के उत्पादन हेतु पहल**

**1967. श्री संभाजी छत्रपती:**

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आयात बिलों को कम करने तथा प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सड़क परिवहन हेतु अनिवार्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए कोई चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) बिजली से चलने वाले वाहनों के उत्पादन और चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना करने हेतु सरकार द्वारा पहले से किये गये प्रयासों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत तथा विदेश में वे बड़े ऑटो विनिर्माता कौन-कौन से हैं जिन्होंने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन में रुचि दर्शायी है?

**उत्तर**
**भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री**
**(श्री बाबुल सुप्रियो)**

**(क) और (ख):** देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने की दृष्टि से भारत सरकार ने 2011 में नेशनल मिशन ऑन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (एनएमईएम) का अनुमोदन किया तथा बाद में वर्ष 2013 में नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 प्रारम्भ किया गया। इस मिशन प्लान को मुख्य रूप से देश में ईंधन सुरक्षा एवं पर्यावरणीय प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। एनएमईएम का उद्देश्य लगभग 9500 मिलियन लीटर के बराबर ईंधन की संचयी बचत करना है ताकि वर्ष 2020 तक 6-7 मिलियन वाहन प्रतिवर्ष बाजार में उतारने के लक्ष्य के साथ-साथ प्रदूषण तथा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 2 मिलियन टन कमी लाई जा सके।

इस मिशन के भाग के रूप में भारी उद्योग विभाग ने एक स्कीम नामतः फेम - इंडिया [भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण] तैयार की है। इस संपूर्ण स्कीम को छह वर्षों की अवधि में, 2020 तक लागू किया जाना प्रस्तावित है जिसमें नियत अवधि के अंत में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए हाइब्रिड/इलेक्ट्रिक वाहन बाजार को विकसित करने तथा इसके विनिर्माण पारिस्थितिकी-तंत्र को बढ़ावा देना अभिप्रेत है। यह स्कीम भारत सरकार की एक हरित पहल है, जो निकट भविष्य में सड़क परिवहन सेक्टर से प्रदूषण को कम करने में सबसे बड़ा योगदान करेगी। इस

स्कीम के 4 फोकस क्षेत्र अर्थात् प्रौद्योगिकी विकास, मांग सृजन, प्रायोगिक परियोजनाएं और चार्जिंग अवसंरचना है।

फेम - इंडिया स्कीम के तहत 01 अप्रैल, 2015 को इसे प्रारम्भ किए जाने से 30 जून, 2017 तक मांग प्रोत्साहन के माध्यम से 148275 इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों (एक्सईवी) को ₹192.56 करोड़ (लगभग) की सहायता दी गई है। इसके परिणामस्वरूप, लगभग 13553917 लीटर ईंधन की बचत हुई है और कार्बन डाइ-ऑक्साइड के उत्सर्जन में 33971052 किलोग्राम की कमी हुई है।

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने फेम - इंडिया स्कीम के विभिन्न फोकस क्षेत्रों के तहत 01 अप्रैल, 2017 को इसे प्रारम्भ किए जाने के बाद वित्तीय सहायता निम्नानुसार प्रदान की है:-

| **क्र.सं.** | **फोकस क्षेत्र/स्कीम के घटक** | **प्रदान की गई वित्तीय सहायता** |
|---|---|---|
| 1 | प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म | ₹38.08 करोड़ |
| 2 | मांग प्रोत्साहन | ₹192.56 करोड़ |
| 3 | चार्जिंग अवसंरचना | ₹1.00 करोड़ |
| 4 | प्रायोगिक परियोजना | ₹36.68 करोड़ |
| **योग** | | **₹268.32 करोड़** |

**(ग):** अपने इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों की बिक्री पर मांग प्रोत्साहन का लाभ लेने के लिए भारी उद्योग विभाग के पास आज की तारीख तक पंजीकृत भारतीय तथा विदेशी ऑटोमोबाइल विनिर्माताओं के नाम नीचे दिए गए हैं:-

1) महिन्द्रा रेवा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रा. लिमिटेड
2) इलेक्ट्रोथर्म (इंडिया) लिमिटेड
3) मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड
4) हीरो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रा. लिमिटेड
5) टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्रा. लिमिटेड
6) लोहिया ऑटो इंडस्ट्रीज
7) एम्पेयर व्हीकल्स प्रा. लिमिटेड
8) एवन साइकिल्स लिमिटेड
9) वॉलवो इंडिया प्रा. लिमिटेड
10) क्रिस मोटर्स
11) अजन्ता मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड
12) महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लिमिटेड
13) टुनवाल इलेक्ट्रोनिक्स
14) ओकीनावा ऑटोटेक प्रा. लिमिटेड

*****